

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 19/19

GCMS NO 2019/00046

1. ग्राम विकास अधिकारी राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नादौती जिला करौली
2. सरपंच ग्राम पंचायत राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली

रेस्पो०

(अपील विरुद्ध मु०नं० 6/18 निर्णय दिनांक 15.2.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती)

अभिभाषक अपीला० श्री ईश्वर सोनी

अभिभाषक रेस्पो० 1 की और से पैरोकार सरकार
रेस्पो० 2 की और से श्री देवी सिंह

अपील संख्या - 13/19

GCMS NO 2019/00023


आम जनता ग्राम मुहाना ,राजाहेडा ग्राम पंचायत राजाहेडा तहसील नादौती जरिये

1. ज्ञान सिंह पुत्र बिरध्या
2. सुबद्धी पुत्र घासीराम जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम मुहाना तहसील नादौती
3. दरब सिंह पुत्र माधोसिंह
4. समय सिंह पुत्र परसादी
5. हुकम सिंह पुत्र ब्रहमोहन
6. भरतराज पुत्र मूलचंद जातियान गुर्जर निवासीयान राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली
2. ग्राम पंचायत राजाहेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत राजाहेडा
3. विकास अधिकारी (ग्राम)राजाहेडा
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति नादौती


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो०

(अपील विरुद्ध मु०नं० 6/18 निर्णय दिनांक 15.2.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती)

अभिभाषक अपीला० श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रेस्पो० 1 की और से पैरोकार सरकार



दिनांक 04.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील दोनो अपीले अपीलांटान की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.2.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती पेश की है ।

दोनो अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो० संख्या संख्या 1 तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण /अपीलांट व रेस्पो० संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत राजाहेडा द्वारा ग्राम मुहाना की जमाबंदी सम्वत 2072 से 75 के खाता संख्या 75 के खाता संख्या 210 के अनुसार ग्राम के खे०न० 164 रकबा 0.12 है०, 165 रकबा 0.14 है०, 189 रकबा 0.29 है०, 191 रकबा 0.12 है०, 192 रकबा 0.44 है०, 193 रकबा 1.94 है०, 194 रकबा 0.80 है० कुल रकबा 3.85 है० की खातेदारी ग्राम पंचायत राजाहेडा अलाटी दर्ज है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 5.2.19 के द्वारा पाया गया कि इस भूमि में जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं। अलग अलग जगह कंकरीट, बजरी, सीमेन्ट की सडक बनाने के काम आने वाले प्लान्ट बने हुए हैं। इस प्रकार यह भूमि कृषि कार्य में नहीं आकर गैर कृषि कार्यों में उपयोग हो रही है। जिस पर अतिक्रमियो द्वारा कब्जा किया हुआ है। भूमि ग्राम पंचायत के काम नहीं आकर अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर भूमि को अकृषि कार्यों में काम लाई जा रही है व भूमि का स्वरूप बिगाड पर खुरद बुर्द किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपील प्राधिकारी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।


अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर


अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणों की अपील पर सुनी गई।

अपील संख्या 19/19 के अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। शिवादाग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत राजाहेडा की कब्जे काशत की आराजी है। अन्य व्यक्तियों का उक्त भूमि से कोई संबंध वास्ता नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा वर्तमान सरपंच परिजन से मिलकर झूठी गलत रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार नादौती को पेश की गई है। जिसके आधार पर तहसीलदार नादौती ने अधिनस्थ न्यायालय में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून से विपरीत होकर स्वीकार किया गया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर भूमि खाली है। सरपंच द्वारा सिवायचक घोषित करवाकर उस पर कब्जा करने की फिराक में है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व प्रार्थी/रेस्पो० के बयान नहीं लिये हैं ना ही अपीलांट को कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय

द्वारा सारी कार्यवाही जल्दबाजी व सरपंच से मिलकर की है। पटवारी हल्का राजाहेडा की उक्त भूमि से संबंधित रिपोर्ट दिनांक 5.2.19 को तहसीलदार के यहाँ पेश की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 177 आर टी एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक वर्ष पूर्व की दिनांक 6.2.18 में दर्ज कर कानून की सरासर अवलेहना की है। इससे स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही शुरू से ही इल्लीगल है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आपस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अपील संख्या 19/19 में रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम मुहाना की जमाबंदी सम्वत 2072 से 75 के खाता संख्या 75 के खाता संख्या 210 के अनुसार ग्राम के ख०न० 164 रकबा 0.12 है०, 165 रकबा 0.14 है०, 189 रकबा 0.29 है०, 191 रकबा 0.12 है०, 192 रकबा 0.44 है०, 193 रकबा 1.94 है०, 194 रकबा 0.80 है० कुल रकबा 3.85 है० जो की खातेदारी ग्राम पंचायत राजाहेडा अलाटी में दर्ज है। उस पर जगह जगह पत्थर पड़े होने एवं एवं कंकरीट, बजरी, सीमेन्ट की सड़क बनाने के प्लान्ट बनाने हेतु बने हुए है जिस पर पटवारी द्वारा दिनांक 5.2.19 को तहसीलदार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर ही तहसीलदार द्वारा धारा 177 आर टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है। भूमि पर पंचायत द्वारा आज तक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 177 आर टी एक्ट के प्रावधानों पर पूर्ण मनन व पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर विधिक विवेचना कर ही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 13/19 में अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि आराजीयात खाता संख्या 210 में वर्णित ख०न० 164, 165, 189, 191, 192, 193, 194 कुल रकबा 3.85 है० जमाबंदी सम्वत 2072-75 में ग्राम पंचायत राजाहेडा के नाम दर्ज है तथा जॉच रिपोर्ट पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति नादौती पर गौर किये बिना फर्द मौका मुहाना में हल्का पटवारी द्वारा जारी रिपोर्ट की बारीकी से विवेचना नहीं की है। संपूर्ण कार्यवाही रेस्पोंडेंट संख्या 1, 2 लगायत 4 से आपसी साझकर सरपंच परिवार को फायदा पहुँचाने की गरज से प्रारंभ की है और तथ्यों को छुपाकर निर्णय पारित करवा लिया गया। पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा निष्कर्ष के कालम में उक्त आराजीयात पर ग्राम मुहाना के प्यार सिंह, हिस्मत सिंह, बनेसिंह पिसरान हीरालाल एवं केदार पुत्र हिम्मत हिंस का कब्जा दर्शाया है तथा रकम बाई पत्नि केदार विगत 15 वर्षों से सरपंच है। उक्त संपूर्ण परिवार ने निर्णय में वर्णित आराजीयात जो ग्राम पंचायत की भूमि है को हटाने की गरज से तथा ट्रेस पास कर कब्जा बनाये रखने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की है। भूमि की खातेदारी संपरिवर्तन करने अधिकार जिला कलेक्टर को है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय प्रारंभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी में आता है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है। आलोच्य निर्णय पक्षपातापूर्ण है जो सरपंच को लाभ पहुँचाने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को हडपने की गरज से रेस्पोंडेंट संख्या 1 से साज करके कराया गया है जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत के नागरिक होने के नाते उक्त भूमि में इनका हित निहित होने से धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से गांव की बेसकिमती भूमि पर लोग कब्जा कर लेगे जिससे ग्राम पंचायत को भारी क्षति होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अपील संख्या 13/19 में रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने बहस अपील में कथन किया कि साबिक ख०न० 204/237 रकबा 15 बीघा जरिये नामा० संख्या 3 द्वारा ग्राम पंचायत राजाहेडा को आवंटित हुई थी। यह भूमि ग्राम पंचायत राजाहेडा को इस उद्देश्य से आवंटित की गई थी कि इस भूमि में ग्राम पंचायत फसल, उपज नीलाम कर आय अर्जित कर विकास कार्य करावे परन्तु मुताबिक रिपोर्ट 6.2.19 ग्राम विकास अधिकारी राजाहेडा का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। आज तक भी फसल नीलाम नहीं की गई है। उक्त भूमि से ग्राम पंचायत ने कभी राजस्व अर्जित नहीं किया व कभी फसल नीलाम नहीं की गई। जिसके मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 5.2.19 द्वारा मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बरान को अतिक्रमियों द्वारा गैर कृषि उपयोग में लिया जाना बताया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।


उक्त दोनों अपीलों पर उभयपक्ष अधिवक्तागणों द्वारा की गई बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम मुहाना के खाता संख्या 210 के ख०न० 164,165,189,191,192,,193,194 कुल रकबा 3.85 है० जमाबंदी सम्वत् 2072-75 में ग्राम पंचायत राजाहेडा अलाटी के नाम दर्ज है। पटवारी हल्का राजाहेडा तहसील नादौती द्वारा भूमि कृषि कार्य में नहीं आकर गैर कृषि कार्य में ली जा रही है। भूमि में जगह लगभग 40 ट्रोली पत्थर पड़े हुए हैं एवं 4 जगहों पर कंकरीट, बजरी सीमेन्ट मिक्सर प्लान्ट बने हुए हैं तथा दीगर व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा जाना रिपोर्ट में अंकित किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से पत्रांक 491 दिनांक 5.2.19 को बिन्दुवार जबाब चाहा गया है। जिसके जबाब में ग्राम विकास अधिकारी राजाहेडा द्वारा दिनांक 6.2.23 को बिन्दुवार जबाब प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 1 के जबाब में अंकित किया है कि उक्त भूमि संबंधी रिकार्ड पूर्व ग्राम पंचायत राजाहेडा द्वारा चार्ज में नहीं दिया गया ना ही मेरे संज्ञान में है। बिन्दु संख्या 2 के संबंध में लिखा है कि संज्ञान के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं की गई, ग्राम पंचायत का कब्जा नहीं रहा है। बिन्दु संख्या 3 के जबाब में अंकित किया है कि संज्ञान के कभी नीलामी नहीं की गई इससे राजस्व अर्जित नहीं हुआ है। बिन्दु संख्या 4 के जबाब में अंकित किया है कि मेरे कार्यकाल के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 6.2.19 को पेश किया गया है जो तहसीलदार के पत्रांक 316 दिनांक 5.2.19 से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र की आदेशिका में दिनांक 6.2.18 अंकित किया गया है। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.2.19 नियत की गई। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने का अंकन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 15.2.19 को अंतिम निर्णय पारित कर आराजीयात को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। जबकि सीपीसी के प्रावधानों के तहत कम से कम 30 दिवस की अवधि तामिल की मानी गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं किया जाना स्पष्ट है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी राजाहेडा द्वारा अपने कर्तव्यों की पालना नहीं की गई है एवं एक राजसेवक होने के नाते उसके जो कर्तव्य थे उनके प्रति नजग एवं जागरूक रहकर कार्य नहीं किया गया है जो राजसेवक की अनुशासनहीनता को दर्शाता है। ग्राम विकास अधिकारी अपनी पंचायत का अधिकारी घोषित है उसे उस पंचायत में निहित समस्त अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि का रक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई ना ही उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के हितों को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है अतः दोनो अपीले स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती के मु0नं0 6/18 निर्णय दिनांक 15.2.19 को आपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियों में पृथक पृथक संलग्न की जावे।

अपील निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(लक्ष्मी कांत बालील)
राजसेवक अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर